for mutual reduction of troops and arms; if so, what is Government's reaction thereto;

(b) what is Government's reaction to Pakistan refusal to renew the trade agreement between two countries since July, 1978 and Mrs. Bhutto's evasive remarks that SAARC was examining this very question; and

(c) what is the present arrangement of trade between the two countries?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH) : (a) Government have seen reports of Prime Minister Ms. Benazir Bhutto's remarks on mutual reduction of troops and arms. Government feel that it is in the mutual interest of India and Pakistan to take steps that would improve the climate of relations between the two countries leading to reduction in their defence spending so that scarce resources could be diverted to developmental activities.

(b) and (c) The India-Pakistan Trade Agreement does not fall within the purview of SAARC and is a purely bilateral issue. Government had approached the Pakistani side for renewal of the India-Pakistan Trade Agreement signed in 1975 when it expired in 1978, but the Pakistani side did not respond positively, while we accord Most Favoured Nation status to Pakistan, the latter has not so far reciprocated despite being a member of GATT.

Retirement of members of India Tourism Development Corporation Board

3417. SHRI V. GOPALSAMY:

SHRI T. R. BALU:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to refer the answer to Unstarred Question 1490 given in the Rajya Sabha on the 8th March, 1969 and state:

(a) what are the names of those non official Directors who retired recently from ITDC Board along with dates of the retirement;

(b) what is criteria for selection of ITDC Board member;

(c) what is term of the Board; and

(d) what is usual strength of ITDC Board?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM (SHRI SHIVRAJ PATIL): (a) The following non-official Directors retired from I.T.D.C. Board with effect from 6-10-1987:

(1)Dr. M. M. Anand

(2) Shri Kali H. Mody

(3) Smt. Kumudesh Bhandari

(b) The criteria laid down by the Bureau of Public Enterprises for selection of ITDC Board members, whether official or non-official is being followed. As per these guidelines, the official part-time Directors are representatives of the administrative Ministry and the Ministry of Finance. Non-official Directors are Scientists, technologists or reputed persons or Directors/Senior officials of other Public Sector Undertaking and their strength is to be restricted to 1/3 of the total strength of the Board.

(c) Two years.

(d) As per the memorandum & Articles of Association of ITDC Ltd., the number of Directors shall not be less than two and more than fifteen.

चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में भारतीय क्षेत्र

3418. **श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख तक भारत का कुल कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र क्षमा-

नुबार चीन और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और कुल कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पाकिस्तान द्वारा चीन को दे दिया गया है और चीन द्वारा निर्मित तिब्बत में सिकियांग से *ल्हासा* तक और भारतीय क्षेत्र में से होकर जाने वाले कारकोरम राज मार्ग की लम्बाई कितनी है;

(ख) 1962 में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या तीसरी दुनिया के देशों से आने वाले पर्यटकों को नियमित करने के वास्ते 18,000 फुट ऊंचे खुजरेब दर्रे से गुजरने वाले पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र से चीन के सिकियांग प्रांत तक फैले राजमार्ग के संबंध में चीन और पाकिस्तान के मध्य कोई समझौता हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; इस विषय में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और देश की सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव होगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) भारतीय प्रदेश का कुल मिला कर 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के गैर कानूनी कब्जे में है ।

भारतीय प्रदेश का लगभग 78,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका, जो कि जम्मू-कश्मीर राज्य में पड़ता है, पाकिस्तान के गैर-कानूनी कब्जे में है । इसके अलावा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का लगभग 5,120 वर्ग किलोमीटर इलाका पाकिस्तान के मार्च, 1963 के तथाकथित चीन के पाकिस्तान समझौते के अन्तर्गत गैर-कानूनी रूप से चीन को दे दिया था ।

कारकोरम राजमार्ग का जो हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पड़ता है, उसकी अनुमानित लम्बाई 460 किलोमीटर है । पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्व में अक्साईचिन होकर जाने वाले किन्जियांग-तिब्बत राजमार्ग की लम्बाई अनुमानतः 230 किलोमीटर है ।

(ख) इस मामले पर भारत सरकार निरन्तर ध्यान रखती आई है ।

(ग) और (घ) सरकार को इस बात की जानकारी है कि चीन और पाकिस्तान ने कारकोरम राजमार्ग पर तीसरे देशों के पर्यटक यातायात को नियमित करने के लिए "प्रोतोकोल" पर हस्ताक्षर किए हैं ।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की गैर-कानूनी गतिविधियों के खिलाफ सरकार ने बार-बार उनसे विरोध प्रकट किया है । और उन्हें बताया है कि समूचा जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है ।

सरकार ऐसी सभी घटनाओं की बराबर समीक्षा करती रहती है, जिनका भारत की सुरक्षा पर असर पड़ता सकता हो ।

Clearance to 'rent-a-car' Scheme

3419. SHRI KAMAL MORARKA:
SHRI YASHWANT SINHA:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether any proposals have been cleared allowing foreign companies to set up joint ventures for promoting rent-a-car scheme; and

(b) if so, what are the details thereof?